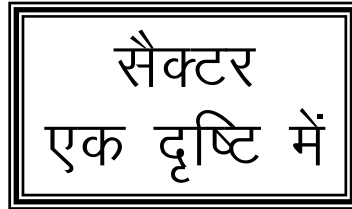


19. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति



वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

● आयोजना बजट सीलिंग राशि	1805.65 लाख
● राज्य आयोजना मद	1805.65 लाख
● केन्द्रीय योजना मद	शुन्य

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- आवश्यक वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति पर निगरानी रखना
- आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ व्यवस्था एवं समुचित निगरानी
- राशन कार्ड उपलब्ध कराना

[kk | , oa ukxfjd vki frl foHkkx dk nf"V i =

15-1 orĕku fLFkfr

■ जिले में कुल उपभोक्ता (राशन कार्ड)	665235
■ एपीएल योजना राशन कार्ड	580546
■ बीपीएल योजना राशन कार्ड	51301
■ अन्त्योदय योजना राशन कार्ड	23388
■ अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड	11739

15-2 X; kj goha i po"khz ; kst uk ds y{; , oa mns' ;

- आवश्यक वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति पर निगरानी रखना
- आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकना
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुदृढ व्यवस्था एवं समुचित निगरानी

15-3 y{; , oa mns' ; ka rd i gq dh j . kuhfr

जिले में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के राशन कार्डों के सीमा के अनुसार आगामी पांच वर्षों में निम्न प्रकार की खाद्यान की आवश्यकता होगी :-

- अन्त्योदय योजना :- जिले में अन्त्योदय अन्न योजना में वर्तमान में 23324 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं 35 किलो प्रतिराशन कार्ड के हिसाब से 816 मै. टन की आवश्यकता है।
- बीपीएल गेहूं/चावल :- जिले में कुल चयनित बीपीएल परिवारों में से अन्त्योदय परिवार घटाने पर 51643 शुद्ध बीपीएल परिवार अवशेष रहते हैं 35 किलो गेहूं/चावल के हिसाब से 1808 मै.टन खाद्यान की प्रतिमाह आवश्यकता है।
- अन्नपूर्णा योजना :- जिले में अन्नपूर्णा अन्न योजना में 11739 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं इन लाभार्थियों हेतु प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान के हिसाब से 118 मै.टन की आवश्यकता है।
- एपीएल गेहू :- जिले में वर्तमान में 580549 एपीएल राशनकार्ड हैं 35 किलो गेहूं/चावल के हिसाब से 20320 मै.टन की मांग बनती है।
- केरोसीन :- जिले में समस्त योजनाओं के राशनकार्डों की संख्या 655516 है 5 लीटर प्रतिराशन कार्ड के हिसाब से प्रति माह 3278 के.एल. केरोसीन की मांग बनती है।
- एल.पी.जी. गैस – जिले में वर्तमान में 16 एलपीजी गैस कम्पनियां कार्यरत हैं तथा 14 कम्पनियां ओर खोली जानी आवश्यक है।

विभागीय योजना मद में 60.74 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जिससे विभागीय लक्ष्य पूर्ण किये जायेंगे।